जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौनसिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 14 संख्याः 225 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 16 जून, 2022 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

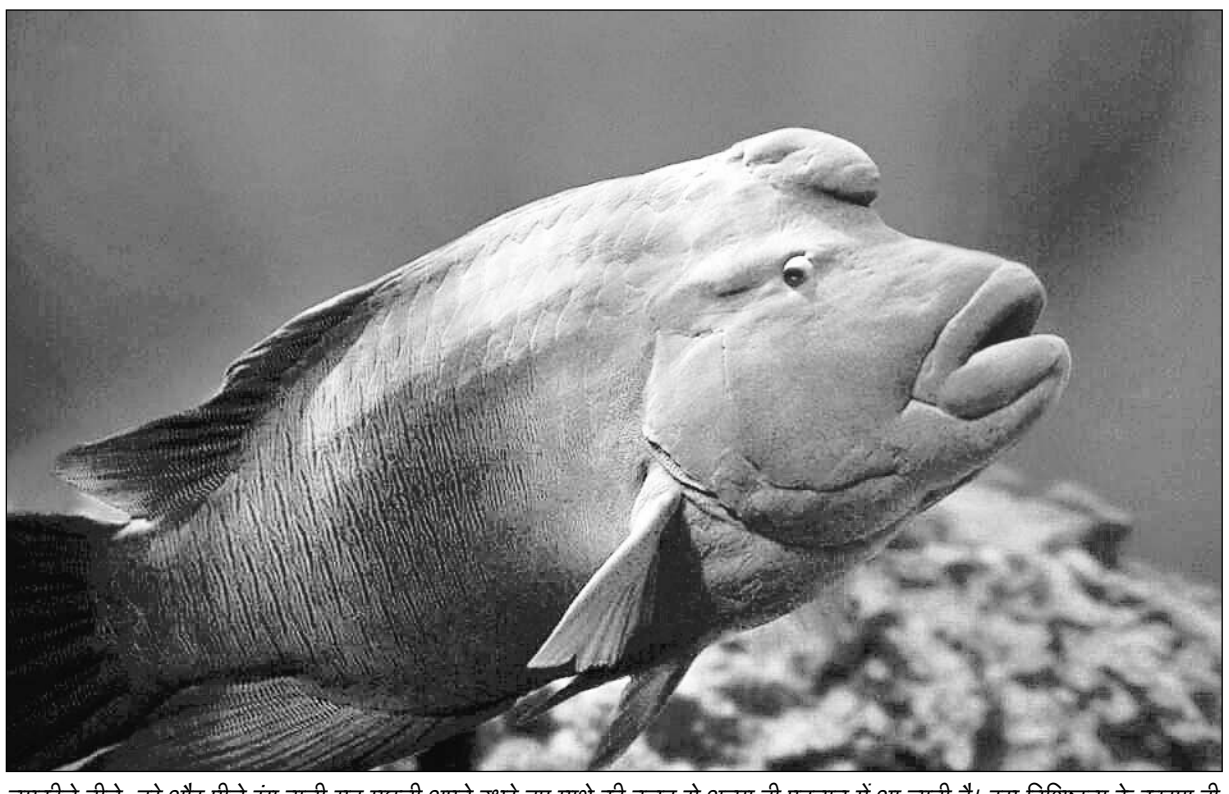

चमकीले नीले, हरे और पीले रंग वाली यह मछली अपने उभरे हुए माथे की वजह से अलग ही पहचान में आ जाती है। इस विशिष्टता के कारण ही इसे ''हम्पहैड'' रैंस कहते हैं। समूचे एशिया पैसिफिक में पाई जाने वाली इस विशालकाय कोरल रीफ मछली का वजन तकरीबन 400 पाउण्ड होता है और यह 6 फीट तक लंबी हो सकती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हाँगकाँग और चीन में इसे भोजन के रुप में बहुत पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर इसकी अवैध फिशिंग हो रही है। इंटरनैशनल यूनियन फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ नेचर, जिसने सबसे पहले वर्ष 2004 में इसे ''एन्डेंजर्ड'' लिस्ट में रखा था, का आकलन है कि ऑस्ट्रेलिया की क्वीन्सलैण्ड रीफ्स में प्रति 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में औसत सिर्फ 2.5 से 3.5 वयस्क हम्पहैड रैंस हैं और शेष रेंज में प्रति दस हजार मीटर क्षेत्र में केवल दस मछलियां ही हैं। वर्ष 2005 में संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध के लिए हुए समझौते, सी.आई.टी.ई.एस. में इन्हें अधिसूचित किया गया था। इन मछलियों को मुख्यतया सबसे बड़ा खतरा जरूरत से ज्यादा फिशिंग से है साथ ही कोरल रीफ इको सिस्टम का हिस्सा होने के नाते ये परिवर्तन से भी प्रभावित हो रही हैं। इन मछलियों को पकड़ने के लिए पारम्परिक रुप से जो तरीके इस्तेमाल किए जाते थे उनमें हुक एवं लाईन, हैण्ड स्पिअर (भाला) और ट्रैप का इस्तेमाल होता था, अब कुछ समय से डाइविंग टैंक के साथ स्पिअर गन्स भी प्रयुक्त हो रही हैं। चूंकि ये मछली बहुत बड़ी हैं और इन्हें पकड़ना मुश्किल है, इसलिए या तो गोताखोर रात में मछली पकड़ते हैं या फिर अवयस्क मछलियों पर फोकस करते हैं, जो थोड़ी छोटी होती हैं। कई क्षेत्रों में तो मछुआरे और भी भयंकर तरीका प्रयुक्त करते हैं, वे मछलियों को बेहोश करने के लिए सायनाइड से एक्सपोज़ करते हैं फिर तुरंत ही मछली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और ताजे पानी में डाल देते हैं, इसके बाद जो सायनाइड पानी में रह जाता है वह कोरल व अन्य जीवों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी भी इनकी अवैध फिशिंग बदस्तूर जारी है। वर्ष 2015 के एक सर्वे में पता चला था कि, जीवित, चिल्ड या फ्रोज़न हम्पहैड रैंस बेचने वाली 15 कंपनियों में 12 चीन की हैं। हम्पहैड रैंस कोरल रीफ के लिए फायदेमंद हैं। ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टार फिश को खाती हैं, जिसका भोजन कोरल हैं, इसलिए हम्पहैड रैंस को बचाकर कोरल रीफ की रक्षा भी की जा सकती है।

पवार राष्ट्रपति का चुनाव न लड़ने के निर्णय पर अडिग रहे

ममता बनर्जी ने बंगाल के पूर्व राज्यपाल व महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी व जम्मू-कश्मीर के पूर्व मु.मंत्री फारूख अब्दुल्ला के नाम का सुझाव दिया, विकल्प के रूप में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जून। मराठा नेता एवं नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) सुप्रीमो शरद पवार बुधवार को भी अपनी बात पर खड़े रहे और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार बनने से इंकार कर दिया, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यहां कॉन्स्टीट्यूशन क्लब एनैक्सी में आयोजित विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग में पवार से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने का अनुरोध किया गया था।

विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में पवार का यह अधिकारिक स्टैण्ड था। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि उनका नाम बार-बार उछालकर उनका मजाक ना बनाया जाए, जबकि वह इसके लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार इंकार कर चुके हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि इंकार के बावजूद उन्हें क्यों तंग किया जा रहा है और वे इन टिप्पणियों से आहत महसूस करते हैं कि उनकी ''ना'' का मतलब ''हाँ'' है।

एन.सी.पी. नेताओं के साथ अपने आवास पर हुई एक पूर्व मीटिंग में उन्होंने कहा कि वह एक ''हारा हुआ युद्ध'' नहीं लड़ना चाहते और आज की तारीख में उनके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि शिव सेना के नेतृत्व वाला महाराष्ट्र का सत्तारूढ़ गठबंधन 5 साल का अपना कार्यकाल पूर्ण करे।

- **शरद पवार ने विपक्ष की बैठक में कहा कि, उन्हें मजाक का पात्र न बनायें, बार-बार उनका नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करके।**
- **पवार ने यह भी कहा कि, बार-बार नाम प्रस्तावित करने से ऐसा लगता है कि, उनकी ''ना'' में ''हाँ'' छिपा है।**
- **विपक्ष की बैठक में ये टिप्पणियां करने से पहले, दिन में एन.सी.पी. के नेताओं से अपने निवास पर बात करते हुए, उन्होंने कहा कि, वे एक ''हारने वाली लड़ायी (चुनाव) नहीं लड़ना चाहते तथा उनके समक्ष इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि, महाराष्ट्र में एन.सी.पी., शिव सेना व कांग्रेस गठबंधन से बनी सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करे।**

17 पार्टियों की मीटिंग में उन्होंने नेताओं से बड़ी रूखाई से कहा कि वे किसी अन्य उम्मीदवार की तलाश करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि ''81 वर्ष की उम्र में भी मैं एक सक्रिय राजनीतिक पारी खेल सकता हूँ।''

मीटिंग आयोजित करने वाली ममता बनर्जी ने पवार का नाम प्रस्तावित किया, जबकि अपने आवास पर ममता के साथ हुई मीटिंग के दौरान वह उन्हें इंकार कर चुके थे। सूत्रों ने बताया कि ममता ने दो अन्य विकल्प सुझाए-एक तो बंगाल के पूर्व राज्यपाल एवं महात्मा गांधी के पोते डॉ. गोपाल कृष्ण गांधी (77) और नैशनल कॉन्फ्रैंस सुप्रीमो एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्लाह (84), डॉ. गांधी वर्ष 2017 में हुए उप राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले युनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार थे और एन.डी.ए. प्रत्याशी एम. वेंकैया नायडू से हार गए थे। डॉ. गांधी को 244 जबकि नायडू को 514 वोट मिले थे।

मीटिंग में तय किया गया कि 21 जून तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का निर्णय कर दिया जाएगा। इसमें तय किया गया कि इसके लिए बीजू जनता दल (बी.जे.डी.), शिरोमणि अकाली दल (एस.ए.डी.) तेलंगाना राष्ट्र समिति (टी.आर.एस.) तथा आम आदमी पार्टी (आप) को भी राजी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बुधवार की मीटिंग में भाग नहीं लिया था। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे और 21 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद, नए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ई.डी. के अफसरों में झुंझलाहट

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जून। समझा जा रहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार तीसरे दिन, कानूनी सलाह पर एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) द्वारा कथित मनी लॉण्डरिंग के बारे में पूछे जा रहे पचीदे प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर दिया।

ई.डी.के अधिकारी 2010 में स्थापित राहुल गांधी की यंग इण्डिया कम्पनी द्वारा कोलकाता की कंपनी डीटॉक्स मर्चैन्डाइस से लिए गए एक करोड़ के लोन के बारे में विभिन्न तरीकों

- **अफसर का कहना है कि, बीस घंटे की पूछताछ के बावजूद उन्हें कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो पायी है, क्योंकि राहुल बड़ा सोच-समझ के, तीखे सवालों का जल्दबाजी में जवाब नहीं दे रहे, जिससे वे कहीं फंसे।**

से प्रश्न पूछकर उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आयकर विभाग ने डीटॉक्स मर्चैन्डाइस के खिलाफ हवाला में लिप्त होने का एक केस खोजा है। उनका प्रयास है, गांधी परिवार द्वारा नैशनल हैरल्ड की 2000 करोड़ की सम्पत्ति हड़पने का केस तैयार करना।

कांग्रेस सूत्रों ने कहा, ई.डी. अधिकारियों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न राजनीति से प्रेरित हैं और राहुल गांधी को उन बेमतलब के असंगत प्रश्नों का जवाब देने का अधिकार है जो कि उनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ई.डी. की सख्ती से पूछताछ जारी रही

मूक सवाल यह उठ रहा है कि, मोदी सरकार क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ में सहयोग न करने के आरोप में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जून। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्रूरता ने सारी हदें पार कर दी और कांग्रेस के नेताओं को सड़कों पर घसीटा गया और गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया, पानी तक नहीं दिया गया। यही नहीं महिला सांसदों के कपड़े फाड़े गए और सबसे बड़ी बात वहां कोई पुलिस अफसर नहीं था जिसे दिल्ली पुलिस की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके।

ई.डी. द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ का आज तीसरा दिन था और सुबह पुलिस 24, अकबर रोड स्तित कांग्रेस मुख्यालय पर जबरन पुलिस घुस आई तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ए.आई.सी.सी. स्टाफ को उठा ले गई तथा विरोध कवर कर रहे मीडिया के साथ भी दुर्व्यवहार किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रैस कॉन्फ्रेंस करने में व्यस्त थे वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ

- **हालांकि गिरफ्तारी से राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति जागने का खतरा भी है तथा राहुल गांधी को प्रताड़ित हीरो की छवि भी मिल जायेगी।**

डटे हुए थे। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बस में बिठाकर अज्ञात स्थान पर ले गई। साथ ही राहुल गांधी से नैशनल हैरल्ड केस में ई.डी. द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में मौन सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस उठा ले गई।

आज लगातार तीसरे दिन ई.डी. ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया और उस केस में पूछताछ की जिसमें उन्हें और उनकी मां सोनिया गांधी को जमानत मिल चुकी है।

मूल प्रश्न यह कि क्या मोदी राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाएंगे क्योंकि ऐसा करना राहुल को हीरो बना देगा या फिर वे गांधी परिवार पर इस केस के जरिए लगातार दबाव बनाए रखेंगे पर किस राजनैतिक उद्देश्य के लिए, यह तो वे ही बता सकते हैं।

जानकार सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी व राहुल के खिलाफ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

5 जी

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जून। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी स्प्रैक्ट्रम के ई ऑक्शन (नीलामी) की मंजूरी दे दी और दूरसंचार विभाग ने बिना कोई समय गंवाए 72 गीगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम की बोली लगाने के लिए नोटिस इन्वाइटिंग एप्लीकेशन (एन.आई.ए.) जारी कर दी। लक्ष्य है कि जुलाई अंत तक 5जी सर्विस लागू कर दी जाए, जो 4जी से दस गुना ज्यादा तेज है।

- **जुलाई के अंत तक 5 जी की सेवा उपलब्ध होने लगेगी।**

नीलामी का नोटिस 20 साल के लिए जारी किया गया है, और बिडर्स को बिना किसी देनदारी के 10 साल बाद स्पैक्ट्रम लौटाने का भी विकल्प दिया गया है। इसके अलावा हर वर्ष 20 समान किश्तों में अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी है। यह कैश प्रवाह की आवश्यकताओं को आसान बनाने और व्यवसाय की लागत कम करने के लिए किया गया है।

यह सरकार के डिजीटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण होगा और इससे मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, टैलीमैडिसन, ई-राशन से लेकर अत्योदय परिवारों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

ममता बनर्जी द्वारा आहूत विपक्ष की बैठक में एकता कम मतभेद ज्यादा नज़र आये

पांच बड़ी पार्टियों, तेलंगाना राष्ट्र समिति, आप, अकाली दल, बी.जे.डी. व डी.एम.के. ने भाग नहीं लिया बैठक में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जून। जैसी कि उम्मीद की जा सकती थी, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए एकता कायम करने का विपक्ष का प्रयास विसंगति के साथ समाप्त हो गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अच्छी-खासी संख्या में वोट रखने वाली पांच बड़ी पार्टियों ने ममता द्वारा आहूत की गई मीटिंग से दूरी बनाए रखने का विकल्प चुना।

दूसरी ओर वे पार्टियां, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से अस्तित्व नहीं हैं, ममता बनर्जी के पाले में आ गई हैं। इस मीटिंग में सी.पी.आई. (एम.), सी.पी.आई., और सी.पी.आई. (एम. एल.) ने अपने प्रतिनिधि भेजे। जिन पार्टियों के विधायकों की विधानसभा में स्ट्रैंथ अच्छी हैं उन्होंने मीटिंग में भाग ना लेने का विकल्प चुना।

अब यह स्पष्ट है कि विपक्ष की एकता की तमाम बातों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी खेमे में एक दूसरे पर हावी होने की आदत के बीच उसकी बाजी

- **कुछ अन्य पार्टियों, जैसे सी.पी.आई., सी.पी.एम. व कांग्रेस ने केवल प्रतिनिधि भेजे।**
- **एक आम शिकायत यह थी कि, विपक्ष की अन्य पार्टियों से बिना सलाह मशविरा किए, एक तरफा निर्णय ले लिया व शरद पवार को उम्मीदवार बनाने की घोषणा क्यों कर दी।**

पलटने की रणनीति पर विजय पा सकती है।

इनमें से एक क्षेत्रीय दिग्गज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने ममता की मीटिंग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। यह निर्णय ना केवल सैद्धांतिक आधार पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को भी ध्यान में रखकर लिया गया। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि ममता बनर्जी ने शरद पवार के नाम की सर्वानुमति वाले प्रत्याशी के रूप में एकतरफा घोषणा कर दी। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टी.आर.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय सरकार की सेना में भर्ती की ''अग्निपथ'' स्कीम का युवाओं ने भी विरोध करना शुरू किया

शुक्रवार को भी पूछताछ

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जून। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट ने नैशनल हैरल्ड मामले में

- **राहुल गांधी को हाजिर होने के लिये कहा गया है।**

तीन दिन कठोर पूछताछ के बाद शुक्रवार को फिर पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है।

बुधवार को उनसे लंच से पहले तीन घंटे तक और फिर 5 घंटे तक पूछताछ की गई।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जून। सैन्य बलों में नई नियुक्ति नीति पर सुरक्षा बलों के परम्परावादी और परिवर्तन विरोधी अधिकारियों के विरोध का सामना कर रही केन्द्र सरकार को युवा वर्ग के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है।

केन्द्र द्वारा शुरु की गई अग्निपथ योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं को चार साल के लिए सेना की तीनों शाखाओं में नियुक्त किया जाएगा और अग्निवीर नाम दिया जाएगा, इनमें से 25 प्रतिशत को अधिकतम 15 साल के लिए सेना में नौकरी दी जाएगी। चार साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्हें 11.7 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसमें इन युवा अग्निवीरों के योगदान के अलावा केन्द्र व राज्य सरकारों का योगदान भी शामिल होगा। इसी के साथ

बिहार के आधा दर्जन रिक्रूटमैंट बोर्ड के दफ्तरों के बाहर सैकड़ों युवा इकट्ठे हुए अपना विरोध जाहिर करने के लिये

- **जैसा कि विदित ही है, सेना के कई रिटायर्ड जनरल, जिनमें ले. जनरल पी.आर. शंकर व ले. जनरल प्रकाश मेनन शामिल हैं, ने काफी कड़े शब्दों में ''अग्निपथ'' स्कीम की आलोचना की है।**
- **यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, अग्निपथ स्कीम के मार्फत 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में चार साल के लिये भर्ती करके सरकार सेना के आधुनिकीकरण के लिये पर्याप्त बजट की व्यवस्था करना चाहती है तथा सरकार का यह भी मानना है कि, इस स्कीम के लागू होने से सैनिकों की औसत आयु, जो फिलहाल 32 साल है, घट कर 25 साल हो जायेगी। जिससे ज्यादा पढ़ा-लिखा सैनिक आधुनिक साइबर आधारित हथियारों के उपयोग को ज्यादा आसानी से समझ सकेगा।-**

सरकार की योजना सिपाही और नौ सेना व वायु सेना में इसी के समकक्ष पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को रोकने की भी है।

रिटायर्ड सेना अधिकारी इस नई भर्ती नीति की गंभीर आलोचना कर रहे हैं। बिहार में आधादर्जन केन्द्रों में सैंकड़ों युवा आज आर्मी स्क्रिूटमैंट्स बोर्ड के समक्ष एकत्रित हुए और रक्षा सेना में ''संविदा'' पर नौकरी देने की नीति का विरोध किया।

रक्षा बलों की आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक है। कुल रक्षा बजट 525,166 करोड़ रू. का है इसमें से 119,696 करोड़ रू. पैंशन मद में और लगभग इतना ही वेतन भुगतान खर्च हो जाता है इसके अलावा कुछ राशि नियमित रख रखाव में भी खर्च होती है, और रक्षा सेनाओं में आधुनिकीकरण व सुधार के लिए बहुत मामूली रकम बचती है। अग्निपथ योजना से रक्षा सेनाओं को खर्चा कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि अग्निवीर पैंशन या किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।

नई योजना की सोशल मीडिया पर भी भारी आलोचना हुई है। लैफ्टिनैंट जनरल विनोद भाटिया ने ट्विटर पर कहा कि यह प्रस्ताव रक्षा सेनाओं के लिए डैथ नैले (मृत्यु की घंटी) के समान है साथ ही इससे सेना का सैन्यकरण होगा। लैफ्टिनैंट जनरल पी.आर. शंकर ने कहा कि अग्निवीर ''बैडली ट्रैन्ड टूरिस्ट्स'' से बेहतर नहीं होंगे। सरकार रक्षा बलों की औसत आयु वर्ष 2030 तक 32 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करना चाहती है और सिर्फ एक चौथाई अग्निवीरों को ही रखा जाएगा। लेकिन बड़ी चिंता यह होगी कि 21 से 25 साल की उम्र में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का क्या होगा। लैफ्टिनैंट जनरल प्रकाश मैनन के अनुसार नई भर्ती नीति के लिए पायलट प्रोजैक्ट लाई है। लेकिन गत 8 सालों के सरकार के फैसलों में देखा जाए तो सरकार ''लर्न वाइल यू रन'' की नीति अपना रखी है।

एफ.आई.आर.

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 जून। कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की। क्योंकि दिल्ली पुलिस आज सुबह बिना अनुमति ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में घुस गई और पार्टी के लोगों के साथ मारपीट की। पार्टी ने सभी संबंधित अधिकारियों को भी निलम्बित करने की मांग की।

- **कांग्रेस ने मांग की कि, दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिये, क्योंकि पुलिस बिना इजाजत के ए.आई.सी.सी. के मुख्यालय में घुस गयी तथा कार्यकर्ता व नेताओं से मारपीट की।**

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह